

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2572/2022

मैसर्स श्री प्रेमपुरजी ग्रानिमारबो प्राइवेट लिमिटेड, जी-185-186, रीको औद्योगिक क्षेत्र, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान, अपने निदेशक श्री अनिल सालेचा के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001 के माध्यम से।
2. प्रमुख आयुक्त सीमा शुल्क, एन.सी.आर. बिल्डिंग, स्टैच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005।
3. मुख्य आयुक्त, राज्य कर, कर भवन, अंबेडकर सर्किल, जयपुर - 302001।
4. उचित कार्यालय, राज्य कर, जयपुर - III, सर्किल-एच, जोनल कर भवन, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर - 302004।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री विक्रम कुमार गोगरा
प्रतिवादी के लिए	:	श्री किंशुक जैन के साथ
		श्री जय उपाध्याय

माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन

माननीय न्यायमूर्ति श्री उमा शंकर व्यास

आदेश

<u>निर्णय आरक्षित किया गया</u>	:: :: ::	<u>14.11.2024</u>
<u>घोषित किया गया</u>	:: :: ::	<u>28.11.2024</u>

अवनीश झिंगन, जे :-

1. यह याचिका प्रतिवादियों को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संक्षेप में 'आईजीएसटी') की वापसी ब्याज सहित जारी करने के निर्देश मांगने के लिए दायर की गई है।
2. याचिकाकर्ता एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और प्राकृतिक पत्थरों का निर्यातक है। भारत संघ, प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क-जयपुर, मुख्य आयुक्त राज्य कर-जयपुर और उचित अधिकारी राज्य कर जयपुर-III को प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
3. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने जुलाई 2017 से सितंबर 2017 की अवधि से संबंधित 17,90,279/- रुपये की आईजीएसटी वापसी का दावा किया था। अभिवचन के अनुसार, वापसी इस आधार पर नहीं दी जा रही है कि याचिकाकर्ता द्वारा 'उच्च दर की शुल्क वापसी' का दावा किया गया था। यह मामला स्थापित किया गया है कि शिपिंग बिलों का विवरण दाखिल करते समय मानवीय त्रुटि के कारण निर्यात किए गए माल के लिए उच्च शुल्क वापसी का दावा किया गया था। वापसी जमा न होने के कारण याचिकाकर्ता ने भारतीय सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात) कस्टम हाउस, मुंद्रा सेज पोर्ट, मुंद्रा और तमिलनाडु और हैदराबाद के सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष शिकायतें उठाईं। एक शिकायत के जवाब के साथ संलग्नक में, यह कहा गया है कि उच्च दर की वापसी का लाभ उठाने के लिए वापसी दाखिल करने का निर्णय लिया गया है। एक अन्य शिकायत का जवाब यह था कि जीएसटी विभाग ने सीमा शुल्क अधिकारियों को आवश्यक विवरण नहीं भेजे हैं। वापसी प्राप्त न होने के कारण रिट याचिका अधिसूचित की गई।
4. प्रतिवादियों ने 09.11.2022 के संक्षिप्त हलफनामे के माध्यम से जवाब दाखिल किया है, जिसमें क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की आपत्ति इस आधार पर उठाई गई है कि वापसी संबंधित निर्यात बंदरगाहों से संबंधित है।
5. 01.05.2023 को, मामले को प्रवेश के लिए और क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए स्थगित कर दिया गया था।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता राजस्थान जीएसटी प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत है; राजस्थान में स्थायी प्रतिष्ठान है और उसे राज्य प्राधिकरणों के क्षेत्राधिकार में आवंटित किया गया है। निवेदन है कि वापसी उचित अधिकारी द्वारा संसाधित की जानी है। यह तर्क देने के लिए परिपत्र संख्या 3/3/2017-जीएसटी दिनांक 05.07.2017 पर भरोसा किया गया है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 (संक्षेप में 'नियम') के नियम 96 के लिए उप-आयुक्त या सहायक आयुक्त केंद्रीय कर उचित अधिकारी है। यह तर्क है कि उच्च दर की शुल्क वापसी के अनजाने में किए गए दावे के लिए वापसी से इनकार नहीं किया जा सकता है। गुजरात उच्च न्यायालय के अवधकृष्ण प्लास्टोमेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ में (2021) 89 जी.एस.टी.आर. 163 में रिपोर्ट किए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसके खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर एसएलपी संख्या 7095/2021 को 30.07.2021 को खारिज कर दिया गया था।

प्रमुख आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, मुंद्रा, कच्छमुंद्रा पोर्ट और एस.पी.एल. आर्थिक क्षेत्र द्वारा पारित 11.10.2022 के आदेश को यह तर्क देने के लिए प्रस्तुत किया गया है कि समान तथ्यों पर अगस्त 2017 की अवधि से संबंधित याचिकाकर्ता की आईजीएसटी वापसी स्वीकृत की गई थी।

7. इसके विपरीत, वापसी के आवेदन को संबंधित निर्यात बंदरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निपटाया जाना है और सूचीबद्ध प्रतिवादियों की आईजीएसटी की वापसी के लिए कोई भूमिका नहीं है।

8. क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के मुद्दे से निपटने के लिए नियम 96 प्रासंगिक है: -

"96. भारत से बाहर निर्यात किए गए माल [या सेवाओं] पर भुगतान किए गए एकीकृत कर की वापसी।

(1) [माल के निर्यातक] द्वारा दायर शिपिंग बिल को भारत से बाहर निर्यात किए गए माल पर भुगतान किए गए एकीकृत कर की वापसी के लिए एक आवेदन माना जाएगा और ऐसा आवेदन तभी दायर किया गया माना जाएगा जब: -

(क) निर्यात माल ले जाने वाले परिवहन साधन का प्रभारी व्यक्ति शिपिंग बिलों या निर्यात बिलों की संख्या और तारीख को कवर करते हुए [एक प्रस्थान घोषणापत्र या] एक निर्यात घोषणापत्र या एक निर्यात रिपोर्ट विधिवत दाखिल करता है; और

(ख) आवेदक ने फॉर्म जी.एस.टी.आर.-3 बी में एक वैध रिटर्न प्रस्तुत किया है:

बशर्ते कि यदि माल के निर्यातक द्वारा शिपिंग बिलों में प्रस्तुत किए गए डेटा और बाहरी आपूर्तियों के विवरण फॉर्म जी.एस.टी.आर.-1 में प्रस्तुत किए गए डेटा के बीच कोई बेमेल है, तो भारत से बाहर निर्यात किए गए माल पर भुगतान किए गए एकीकृत कर की वापसी के लिए ऐसा आवेदन उस तारीख को दायर किया गया माना जाएगा जब उक्त शिपिंग बिल के संबंध में ऐसी बेमेलता निर्यातक द्वारा ठीक कर दी जाती है।

(ग) आवेदक ने नियम 10 बी में प्रदान किए गए तरीके से आधार प्रमाणीकरण कराया है;

(2) फॉर्म जी.एस.टी.आर.-1 में निहित [माल के निर्यात के संबंध में प्रासंगिक निर्यात चालानों] का विवरण सामान्य पोर्टल द्वारा सीमा शुल्क द्वारा नामित प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाएगा और उक्त प्रणाली सामान्य पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक पुष्टि प्रेषित करेगी कि उक्त चालानों द्वारा कवर किए गए माल को भारत से बाहर निर्यात किया गया है:

(xxxxx)

(3) फॉर्म जी.एस.टी.आर.-3 या फॉर्म जी.एस.टी.आर.-3 बी में एक वैध रिटर्न प्रस्तुत करने के संबंध में सामान्य पोर्टल से जानकारी प्राप्त होने पर, जैसा भी मामला हो, [सीमा शुल्क द्वारा नामित प्रणाली या सीमा शुल्क का उचित अधिकारी, जैसा भी मामला हो,

निर्यात माल के संबंध में वापसी के दावे को संसाधित करेगा]
और प्रत्येक शिपिंग बिल या निर्यात बिल के संबंध में भुगतान
किए गए एकीकृत कर के बराबर राशि आवेदक के पंजीकरण
विवरण में उल्लिखित और सीमा शुल्क अधिकारियों को सूचित
उसके बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा की जाएगी।

(4) वापसी का दावा रोक दिया जाएगा जहां, -

(क) केंद्रीय कर, राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर के
क्षेत्राधिकार आयुक्त से उप-धारा (10) या धारा 54 की उप-धारा
(11) के प्रावधानों के अनुसार वापसी का दावा करने वाले व्यक्ति
को भुगतान रोकने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; या

(ख) सीमा शुल्क का उचित अधिकारी यह निर्धारित करता है कि
माल का निर्यात सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के
उल्लंघन में किया गया था।" XX XX XX

9. नियम 96 भारत से बाहर निर्यात किए गए माल पर भुगतान किए गए आईजीएसटी
की वापसी से संबंधित है।

उप-नियम (1) माल के निर्यातक द्वारा दायर शिपिंग बिल को निर्यात किए गए
माल पर भुगतान किए गए आईजीएसटी की वापसी के लिए आवेदन माना जाने की
विधिक कल्पना प्रदान करता है। विधिक कल्पना निम्नलिखित के अधीन है: - (i)
निर्यात माल ले जाने वाले परिवहन साधन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा शिपिंग बिलों या
निर्यात बिल की संख्या और तारीख को कवर करते हुए प्रस्थान घोषणापत्र या निर्यात
घोषणापत्र या एक निर्यात रिपोर्ट दाखिल करना; (ii) फॉर्म जी.एस.टी.आर.-3 बी में एक
वैध रिटर्न प्रस्तुत करना; और (iii) आवेदक का नियम 10-बी के अनुसार आधार
प्रमाणीकरण किया जाना।

उप-नियम (2) फॉर्म जी.एस.टी.आर.-1 में प्रासंगिक निर्यात चालानों के
इलेक्ट्रॉनिक संचरण को सीमा शुल्क द्वारा डिज़ाइन की गई प्रणाली को और सीमा शुल्क

प्रणाली द्वारा सामान्य पोर्टल को चालान किए गए माल के भारत से बाहर निर्यात होने की पुष्टि के लिए आगे संचरण का प्रावधान करता है।

उप-नियम (3) यह प्रावधान करता है कि सीमा शुल्क द्वारा नामित प्रणाली या सीमा शुल्क का उचित अधिकारी, सामान्य पोर्टल से यह जानकारी प्राप्त होने पर कि आवेदक ने फॉर्म जी.एस.टी.आर.-3 बी में वैध रिटर्न प्रस्तुत किया है, निर्यात किए गए माल के संबंध में आईजीएसटी की वापसी के दावे को संसाधित करेगा। प्रत्येक शिपिंग बिल या निर्यात बिल के संबंध में भुगतान किए गए आईजीएसटी के बराबर राशि आवेदक के पंजीकरण में उल्लिखित और सीमा शुल्क प्राधिकरणों को सूचित उसके बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा की जाएगी।

उप-नियम (4) वापसी को रोकने से संबंधित है।

उप-नियम (5 ए) और (5 बी) उप-नियम (4) खंड ए, बी और सी के तहत वापसी को रोकने के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

XX XX XX

10. सबसे पहले, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अभाव में इस रिट याचिका की विचारणीयता के मुद्दे पर विचार किया जाना है।

11. नवंबर 2022 में क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का मुद्दा उठाते हुए जवाब दाखिल करने के बावजूद कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया।

12. यह एक सुस्थापित विधि है कि रिट याचिका पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए, याचिका में किए गए कथनों के आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचना होगा और उन्हें सत्य और सही मानना होगा।

13. रिट में अभिवचन के अनुसार: -

(i) याचिकाकर्ता प्राकृतिक पत्थरों का निर्यातक है और सीमा शुल्क निकासी के माध्यम से नियमित रूप से निर्यात करता है।

(ii) शिपिंग बिल पोर्टल पर अपलोड किए गए थे।

(iii) माल का निर्यात मुंद्रा सेज पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट, कट्टुपल्ली, न्हावा शेवा पोर्ट से किया गया था।

14. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि माल का निर्यात उन बंदरगाहों से किया गया था जो राजस्थान के क्षेत्राधिकार में नहीं थे। निर्यात के लिए दस्तावेज बंदरगाह पर दाखिल किए गए थे।

15. सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य बनाम अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एंड अन्य में (2002) 1 एससीसी 567 में रिपोर्ट किए गए मामले में आयात और निर्यात नीति के अनुसार पासबुक योजना के लाभ के दावे के मामले में क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर विचार किया। निर्यात चेन्नई बंदरगाह के माध्यम से अहमदाबाद में व्यवसाय करने वाले एक निर्यातक द्वारा किया गया था। निर्यात आदेश और दस्तावेज अहमदाबाद में तैयार किए गए थे। लाभ न मिलने से अहमदाबाद में व्यवसाय प्रभावित हुआ। अभिवचन किए गए तथ्यों को विवाद से कोई संबंध नहीं माना गया, अहमदाबाद में न्यायालय के लिए पासबुक योजना के लाभ से इनकार के मुद्दे पर न्यायनिर्णय करने के लिए गुजरात राज्य में कोई कारण कार्यवाही उत्पन्न नहीं हुई। प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत किए गए हैं: -

"12. अब हम यह जांच करेंगे कि आवेदनों के पैराग्राफ 16 में या पूरे विशेष सिविल आवेदनों में उल्लिखित कोई भी तथ्य अहमदाबाद में कारण कार्यवाही के किसी भी हिस्से को जन्म देगा या नहीं, कम से कम अहमदाबाद में उच्च न्यायालय को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से। इस स्तर पर, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि सिविल आवेदनों में कोई भी प्रतिवादी (यहां अपीलकर्ता) अहमदाबाद में स्थित नहीं है। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नगत पासबुक, जिसका लाभ प्रतिवादी सिविल आवेदनों में मांग रहा है, चेन्नई में स्थित एक प्राधिकरण द्वारा जारी की जाती है। नामित प्राधिकारी जो पासबुक योजना से संबंधित मामलों के संबंध में सक्षम व्यक्ति है और जो योजना के तहत विभिन्न कार्य करता है, वह भी

चेन्नई में स्थित है। संबंधित योजना के तहत पासबुक में प्रविष्टियां चेन्नई में अधिकारियों द्वारा की जानी हैं। प्रतिवादियों द्वारा किए गए झींगा का निर्यात और इनपुट का आयात, जिसका लाभ प्रतिवादी आवेदनों में मांग रहे हैं, भी उसी बंदरगाह यानी चेन्नई के माध्यम से किया जाना होगा।

13. उपरोक्त स्वीकृत तथ्यों के बावजूद, यहां प्रतिवादी यह अभिवचन करते हैं कि विशेष सिविल आवेदन के पैराग्राफ 16 में उनके द्वारा उठाए गए अभिवचन के अनुसार, निम्नलिखित तथ्य अहमदाबाद में न्यायालय को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान करने वाली कारण कार्यवाही को जन्म देते हैं। वे हैं: -

(i) प्रतिवादी अहमदाबाद से अपने निर्यात और आयात का व्यवसाय करते हैं;

(ii) उनके निर्यात और आयात के आदेश अहमदाबाद से दिए जाते हैं और अहमदाबाद में निष्पादित किए जाते हैं;

(iii) निर्यात और आयात के लिए दस्तावेज और भुगतान अहमदाबाद में भेजे/किए जाते हैं;

(iv) निर्यात के संबंध में दावा किए गए शुल्क का क्रेडिट अहमदाबाद से संभाला गया था क्योंकि निर्यात आदेश अहमदाबाद में प्राप्त हुए थे और भुगतान भी अहमदाबाद में प्राप्त हुए थे;

(v) पासबुक में क्रेडिट का गैर-अनुदान और उपयोग से इनकार अहमदाबाद में प्रतिवादियों के व्यवसाय को प्रभावित करेगा;

(vi) प्रतिवादियों ने अहमदाबाद में अपने बैंकों के माध्यम से एक बैंक गारंटी के साथ-साथ अहमदाबाद में एक बॉन्ड भी निष्पादित किया है।

14. यद्यपि आवेदन के पैरा 16 में यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ताओं का कार्यालय अहमदाबाद में है, उस तर्क पर जोर

नहीं दिया गया है क्योंकि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि इनमें से किसी भी अपीलकर्ता का कार्यालय अहमदाबाद में नहीं है। इस तथ्य के अलावा, यदि हम प्रतिवादियों द्वारा अभिवचन किए गए कारण कार्यवाही के समर्थन में ऊपर उल्लिखित अन्य तथ्यों पर विचार करते हैं, तो यह देखा जाता है कि इनमें से कोई भी तथ्य सिविल आवेदनों में प्रतिवादियों द्वारा मांगी गई राहत से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है ताकि अहमदाबाद में कारण कार्यवाही का गठन हो सके।

15. भारत के संविधान का अनुच्छेद 226(2) जो उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की बात करता है, पढ़ता है: -

226(2) खंड (1) द्वारा किसी भी सरकार, प्राधिकरण या व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है जो उन क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए कारण कार्यवाही, पूर्ण या आंशिक रूप से, उत्पन्न होती है, भले ही ऐसी सरकार या प्राधिकरण का स्थान या ऐसे व्यक्ति का निवास उन क्षेत्रों के भीतर न हो।

16. उपरोक्त संवैधानिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि एक उच्च न्यायालय उन क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है जिनके भीतर कारण कार्यवाही, पूर्ण या आंशिक रूप से, उत्पन्न होती है। संविधान में यह प्रावधान इस न्यायालय के समक्ष कई मामलों में विचार के लिए आया है। इस संबंध में, हमें ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन बनाम उत्पल कुमार बसु एंड अन्य (1994 4 एससीसी 711 एट 713) के मामले में इस न्यायालय के अवलोकनों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा जिसमें यह माना गया था:

अनुच्छेद 226 के तहत एक उच्च न्यायालय संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है यदि कारण कार्यवाही, पूर्ण या आंशिक रूप से, उन क्षेत्रों के भीतर उत्पन्न हुई हो जिनके संबंध में यह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, भले ही सरकार या प्राधिकरण का स्थान या उस व्यक्ति का निवास जिसके खिलाफ निर्देश, आदेश या रिट जारी किया गया है, उन क्षेत्रों के भीतर न हो। अभिव्यक्ति कारण कार्यवाही का अर्थ उन तथ्यों का समूह है जिन्हें याचिकाकर्ता को साबित करना होगा, यदि विवादित हो, तो न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में निर्णय का हकदार होने के लिए।

इसलिए, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की कमी की आपत्ति का निर्धारण करते समय न्यायालय को कारण कार्यवाही के समर्थन में अभिवचन किए गए सभी तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए, भले ही उक्त तथ्यों की शुद्धता या अन्यथा की जांच न की जाए। इस प्रकार क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का प्रश्न याचिका में अभिवचन किए गए तथ्यों पर तय किया जाना चाहिए, याचिका में किए गए कथनों की सत्यता या अन्यथा अप्रासंगिक है।

17. उपरोक्त से यह देखा जाता है कि एक उच्च न्यायालय को रिट याचिका या इस मामले में एक विशेष सिविल आवेदन पर विचार करने के लिए क्षेत्राधिकार प्रदान करने के लिए, उच्च न्यायालय को कारण कार्यवाही के समर्थन में अभिवचन किए गए सभी तथ्यों से संतुष्ट होना चाहिए कि वे तथ्य एक कारण का गठन करते हैं ताकि न्यायालय को एक विवाद का निर्णय करने का अधिकार मिल सके जो, कम से कम आंशिक रूप से, उसके क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न हुआ है। उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों द्वारा उनके आवेदन में अभिवचन किया गया

प्रत्येक तथ्य अपने आप में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि वे तथ्य न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर कारण कार्यवाही को जन्म देते हैं, जब तक कि अभिवचन किए गए तथ्य ऐसे न हों जिनका मामले में शामिल विवाद से कोई संबंध या प्रासंगिकता न हो। ऐसे तथ्य जिनका विवाद या मामले में शामिल विवाद से कोई संबंध नहीं है, कारण कार्यवाही को जन्म नहीं देते हैं ताकि संबंधित न्यायालय को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान किया जा सके। यदि हम इस सिद्धांत को लागू करते हैं तो हम देखते हैं कि याचिका के पैराग्राफ 16 में अभिवचन किए गए कोई भी तथ्य, हमारी राय में, उन तथ्यों के समूह की श्रेणी में नहीं आते हैं जो एक कारण कार्यवाही का गठन करेंगे जिससे एक विवाद उत्पन्न होगा जो अहमदाबाद में न्यायालयों को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान कर सकता है।

18. जैसा कि हमने पहले देखा है, यह तथ्य कि प्रतिवादी निर्यात और आयात का व्यवसाय कर रहे हैं या वे अहमदाबाद में निर्यात और आयात के आदेश प्राप्त कर रहे हैं या उनके निर्यात और आयात के लिए दस्तावेज और भुगतान अहमदाबाद में भेजे/किए जाते हैं, आवेदनों में शामिल विवाद से कोई संबंध नहीं रखते हैं। इसी तरह, यह तथ्य कि चेन्नई से किए गए निर्यात के संबंध में दावा किए गए शुल्क का क्रेडिट प्रतिवादियों द्वारा अहमदाबाद से संभाला गया था, का भी आवेदन में चुनौती दी गई अपीलकर्ताओं की कार्रवाइयों से कोई संबंध नहीं है। पासबुक में क्रेडिट का गैर-अनुदान और इनकार का अहमदाबाद में प्रतिवादियों के व्यवसाय पर कोई अंतिम प्रभाव, यदि कोई हो, भी हमारी राय में, अहमदाबाद में किसी न्यायालय को अपीलकर्ताओं के खिलाफ शिकायत की गई कार्रवाइयों पर न्यायनिर्णय करने के लिए ऐसी कोई कारण कार्यवाही को जन्म नहीं देगा।

16. सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ गोवा बनाम समिट ऑनलाइन ट्रेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड अन्य में (2023) 7 एससीसी 791 में सिक्किम उच्च न्यायालय में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाले मामले से निपटते हुए, इस आधार पर याचिका की विचारणीयता का दावा किया कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी सिक्किम उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में स्थित हैं, यह माना: -

"11. उच्च न्यायालय ने, चुनौती दिए गए निर्णय और आदेश को सुनाते हुए, यह माना कि रिट याचिकाकर्ता न केवल सीजीएसटी अधिनियम के तहत अपीलकर्ता द्वारा जारी चुनौती दी गई अधिसूचना से व्यथित थे, बल्कि सिक्किम राज्य द्वारा आयोजित, प्रचारित और संचालित लॉटरी पर कर (जीएसटी) लगाने की मांग करने वाले सीजीएसटी अधिनियम के साथ-साथ आईजीएसटी अधिनियम के तहत चुनौती दी गई अधिसूचनाएं जारी करने के केंद्र सरकार के कार्य से भी व्यथित थे। उच्च न्यायालय ने आगे नोट किया कि रिट याचिकाओं में सीजीएसटी अधिनियम के तहत जीएसटी की वास्तविक घटना को चुनौती नहीं दी गई थी, बल्कि संसद के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकारों, जिसमें गोवा राज्य भी शामिल है, द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा उन्होंने लॉटरी पर जीएसटी लगाने की मांग की थी। रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय का यह भी विचार था कि, कम से कम, कारण कार्यवाही का एक हिस्सा उसके क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ था। उच्च न्यायालय का यह भी विचार था कि चूंकि 17 जुलाई, 2017 को डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 36 और 38 ऑफ 2017 पर नोटिस जारी किया गया था, जो 28 सितंबर, 2017 को गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 759/2017 में नियम जारी करने से बहुत पहले था, इसलिए अपीलकर्ता द्वारा विलोपन

के लिए कोई आधार स्थापित नहीं किया गया था; इसलिए, विलोपन की मांग करने वाले अंतरिम आवेदन खारिज कर दिए गए।

12. रिट याचिका पर विचार करने और उसका न्यायनिर्णय करने के लिए उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के समर्थन में, याचिकाकर्ता कंपनी ने यह कहा है:

"29. कि इस माननीय न्यायालय को उक्त रिट याचिका पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है क्योंकि कारण कार्यवाही केवल सिविल में उत्पन्न होती है। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों इस माननीय उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में स्थित हैं।" इन दो वाक्यों के अलावा, उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के समर्थन में और कुछ भी अभिकथन नहीं किया गया है।

13. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता कंपनी के अनुसार कारण कार्यवाही केवल सिविल में उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ है कि कारण कार्यवाही का पूरा हिस्सा और उसका कोई हिस्सा नहीं; इसके अतिरिक्त, यह कहा गया है कि सभी प्रतिवादी उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में स्थित हैं जो तथ्यात्मक रूप से गलत है।

XX XX XX

16. 'कारण कार्यवाही' अभिव्यक्ति को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, लॉर्ड ब्रेट द्वारा कुक बनाम गिल में दी गई 'कारण कार्यवाही' की शास्त्रीय परिभाषा कि "कारण कार्यवाही का अर्थ प्रत्येक तथ्य है जिसे वादी को साबित करना होगा, यदि विवादित हो, ताकि न्यायालय के निर्णय के अपने अधिकार का समर्थन कर सके", को इस न्यायालय द्वारा कुछ निर्णयों में स्वीकार किया गया है। यह स्वयंसिद्ध है कि कारण के बिना कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हालांकि, एक रिट याचिका के संदर्भ में,

ऐसी 'कारण कार्यवाही' का गठन करने वाले तात्त्विक तथ्य वे हैं जो रिट याचिकाकर्ता के लिए दावा की गई राहत प्राप्त करने के लिए अभिवचन और साबित करना अनिवार्य है।

17. यह प्रश्न निर्धारित करना कि क्या अभिवचन किए गए तथ्य कारण कार्यवाही का एक हिस्सा बनाते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (2) को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है, में उच्च न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित करने का एक अभ्यास शामिल होगा कि अभिवचन किए गए तथ्य कारण कार्यवाही का एक तात्त्विक, आवश्यक या अभिन्न अंग हैं। ऐसा निर्धारण करते समय, मामले का सार प्रासंगिक होता है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकलता है कि रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान करने वाले पक्ष को यह खुलासा करना होगा कि कारण कार्यवाही के समर्थन में अभिवचन किए गए अभिन्न तथ्य एक कारण का गठन करते हैं जो उच्च न्यायालय को विवाद का निर्णय करने का अधिकार देता है और यह कि, कम से कम, उच्च न्यायालय में जाने के लिए कारण कार्यवाही का एक हिस्सा उसके क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ। ऐसे अभिवचन किए गए तथ्यों का चुनौती के विषय वस्तु के साथ एक संबंध होना चाहिए जिसके आधार पर प्रार्थना प्रदान की जा सकती है। वे तथ्य जो प्रार्थना प्रदान करने के लिए प्रासंगिक या संगत नहीं हैं, वे न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान करने वाली कारण कार्यवाही को जन्म नहीं देंगे। ये मार्गदर्शक परीक्षण हैं।"

(जोर दिया गया)

17. वर्तमान मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए यह अभिवचन किया गया है कि याचिकाकर्ता राजस्थान में व्यवसाय कर रहा है, राजस्थान में जीएसटी प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत है और राजस्थान में उसका

मूल्यांकन किया जा रहा है। राजस्थान राज्य में उत्पन्न होने वाली कारण कार्यवाही या कारण कार्यवाही के हिस्से के लिए कोई और अभिवचन नहीं किया गया है।

18. नियम 96 (3) के तहत, आवेदक द्वारा फॉर्म जी.एस.टी.आर.-3(बी) में वैध रिटर्न दाखिल करने की जानकारी प्राप्त होने पर वापसी का दावा सीमा शुल्क द्वारा नामित प्रणाली या सीमा शुल्क के उचित अधिकारी द्वारा संसाधित किया जाएगा। इसका व्युत्पन्न यह है कि यदि वापसी के दावे को प्रणाली द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं निपटाया जाता है, तो उसे उस बंदरगाह के सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा विचार किया जाना चाहिए जहां से माल का निर्यात किया गया है। याचिकाकर्ता इस स्थिति से अवगत है और उसने उन बंदरगाहों के भारतीय सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात) के समक्ष वापसी न मिलने की शिकायतों को उठाया था जहां से माल का निर्यात किया गया था।

19. एक अन्य पहलू यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क देने के लिए जिस 11.10.2022 के आदेश पर भरोसा किया गया है कि अगस्त 2017 की अवधि के लिए इसी तरह की वापसी की अनुमति दी गई है, वापसी को मंजूरी देने वाला आदेश आयुक्त (वापसी) कस्टम हाउस, मुंद्रा द्वारा पारित किया गया था।

20. याचिकाकर्ता का राजस्थान में व्यवसाय करना या राजस्थान में जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना, उस बंदरगाह के सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा वापसी न मिलने के लिए राजस्थान में कारण कार्यवाही को जन्म नहीं देता है जहां से माल का निर्यात किया गया था।

21. यह तर्क देने के लिए 05.07.2017 के परिपत्र पर भरोसा करना कि केंद्रीय कर का उप या सहायक आयुक्त नियम 96 के लिए उचित अधिकारी है, गलत है। 2017 की अधिसूचना नियम 96(6) के संबंध में थी जिसे 01.07.2017 से हटा दिया गया था। उप-नियम उप-नियम (5) के तहत वापसी को रोकने के मामले में केंद्रीय कर या राज्य कर के उचित अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के मामले से संबंधित था। उप-नियम माल के निर्यात के कारण उत्पन्न होने वाले आईजीएसटी की वापसी के लिए प्रासंगिक नहीं था।

22. वापसी न मिलने के लिए राजस्थान राज्य में उत्पन्न होने वाली कारण कार्यवाही या कारण कार्यवाही के हिस्से के लिए किसी भी अभिवचन के अभाव में और इस तथ्य

के मद्देनजर कि वापसी के लिए आवेदन निर्यात के बंदरगाहों पर किया गया था और दावे को बंदरगाह के सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा निपटाया जाना है, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अभाव के कारण रिट याचिका खारिज की जाती है।

23. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अभाव के कारण रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है, हमारे लिए इस मुद्दे से निपटने का कोई अवसर नहीं है कि क्या याचिकाकर्ता उच्च दर की शुल्क वापसी का दावा करने के बावजूद आईजीएसटी की वापसी का हकदार है।

24. रिट याचिका खारिज की जाती है।

(उमा शंकर व्यास), जे

(अवनीश झिंगन), जे

बृजेश/एस-1s

रिपोर्ट करने योग्य: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

MITALI KARWA, ADVOCATE

Office At-

O.N. 417, 4th Floor, Sunny Paradise, Tonk Road

Jaipur- 302018

M:- (+91)9001197999

R/5754/2022

Mitali